

## Social Security - (3).

भारत में सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी उपाय  
Social Security Measures in India.

भारत में सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी उपाय सरकार द्वारा ही विभिन्न अधिनियमों के पारित करने के रूप में किये गए हैं। वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा के लिए निम्नलिखित अधिनियम लागू हैं:

(1) श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 →

भारत में सामाजिक सुरक्षा की दिशा में यह पहला कदम था जबकि क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में पारित कर लागू किया गया। यदि कोई श्रमिक कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसको या उसके आश्रितों को इस अधिनियम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था है। अब यह अधिनियम संख्या के सभी श्रमिकों पर लागू होता है चाहे उनका वेतन कितना ही क्यों न हो। वे श्रमिक जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कोई आश्रित लाभ या अशोषिता लाभ पाने के अधिकारी हैं उन्हें भी क्षतिपूर्ति सम्बोधित अधिनियम 1923 के अन्तर्गत कोई सुविधा नहीं मिलेगी।

(2) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 :-

सामाजिक सुरक्षा की दिशा में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अधिनियम उन सभी गैर-मौलिक कारखानों पर लागू होता है जिनमें शक्ति के साथ 10 या उससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं या बिना शक्ति के 20 या उससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं। यह अधिनियम सिनेमा, दुकानों, होटलों, मोटर परिवहन प्रतिष्ठान, समाचार-पत्र प्रतिष्ठान, अदि पर भी लागू होता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत उन कर्मचारियों को लाभ मिलता है जिनका वेतन ₹500 रुपये से अधिक नहीं है। इस अधिनियम के अन्तर्गत कर्मचारियों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं

- (1) बीमारी लाभ
- (2) प्रसूति लाभ
- (3) अशौच्यता लाभ
- (4) आश्रित लाभ
- (5) पिकिलेना सुविधा ।

इस योजना का प्रबंधन स्वयं-शासित निगम द्वारा किया जाता है जिसके 39 सदस्य हैं जो सरकार, उद्योगपति एवं श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 13 सदस्यों की एक कार्यवाहक समिति है। इस निगम

की आध सरकारी अनुदान एवं  
आमिकों तथा उद्योगपतियों के चन्दे  
ले होती है। आमिकों द्वारा किये  
जाने वाले चन्दा वेतन का 1.5%  
प्रतिमाह है। मालिक द्वारा की आमिक  
के वेतन के आधा पर चन्दा वेतन  
का 4 प्रतिशत दिया जाता है।

To be continued.  
Thank you.